मोदी जी बस करो, बहुत हो गया, ज्यादा स्मार्ट बनाओगे तो पलायन हो सकता है

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहरवासी पहले तो नगर निगम से ही परेशान थे अब उनकी परेशानी बढाने के लिये खट्टर सरकार ने उनके सिर पर एफ़एमडीए व स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी नामक दो जिन्न और बैठा दिये। इनकी खुराक के लिये सरकार ने हजारों करोड़ रुपया भी इन्हें दे दिया है। काम करने के नाम पर ये दो ही काम जानते हैं सड़के व सीवर खोदना व बनाना। इसके लिये टेंडर छोड़ना, बिल पास करना व अपने हिस्से का कमिशन बटोरना।

इस काम को भी ये लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बीते दो वर्षों से तो एनआईटी क्षेत्र की लगभग तमाम सड़कें गड्ढों में परिवर्तित हो जाने के चलते आवागमन दूभर हो चुका है। धूल उड़ाती इन सड़कों ने सांस लेना भी दूभर कर दिया है। गर्मी के इन दिनों में भी, बिना पराली जले, धुएं तथा धूल का गुबार शहर भर के ऊपर छाया रहता है। घोषणाएं होती हैं, नारियल फूटते हैं लेकिन काम कोई हुआ नजर नहीं आता।

'हूडा' के तमाम सेक्टरों यानी सेक्टर 4 से लेकर 37 तक की सड़कों का बुरा हाल कर दिया गया है। सेक्टर 11 व 6 की विभाजक सड़क जो मथुरा रोड को बाइपास से जोड़ती है बीते करीब दो साल से खोद कर छोड़ दी गई है। इसी सड़क से कचहरी को जाने वाली सेक्टर 10 व 11 की विभाजक सड़क भी बीते करीब तीन साल से बेहाल पड़ी है। सेक्टर 7 की ओर से इस सड़क पर चलें तो करीब 100 मीटर की सिमेंट रोड इस खतरनाक ढंग से बनाई गई है कि रात के अंधेरे में आये दिन अनेकों वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। इस सड़क के बीच में डिवाइडर के नाम पर करीब डेढ फुट का गैप छोड़ा हुआ है। इस गैप की गहराई भी करीब 9 इंच है जिसे रात के अंधेरे में देख पाना सम्भव नहीं है। परिणामस्वरूप ज्यों ही किसी वाहन का पहिया इस गैप में गिरता है तो होती है दुर्घटना। दो पहिया वाहन के मामले में तो यह और भी घातक हो जाती है।

इसके बाद बाटा मोड़ से बाइपास को जोड़ने वाली कचहरी रोड भी बीते दो माह से निर्माणाधीन चल रही है। बमुश्किल दो सप्ताह का यह काम कई महीनों का प्रोजेक्ट बना दिया गया है। इसी तरह मथुरा रोड को बाइपास से जोड़ने वाली सेक्टर 15-16 की विभाजक सड़क, सेक्टर 17-18 की विभाजक सड़क तथा सेक्टर 19-28 की विभाजक सड़क भी स्मार्ट होने के नाम पर जनता का सिर दर्द बनी हुई है। लगता है कि जनता को परेशान करने के लिये इतना सब काफ़ी नहीं था तो सेक्टरों के बीच-बीच में भी कई सड़कें खोद डाली गई हैं। किसी को पता नहीं चलता कि कब और कहां कोई सड़क बंद हो जायेगी। काफ़ी-काफ़ी दूर जाकर लोगों को वापस मुड़ना पड़ता है। इन सबके चलते सेक्टरों के भीतर प्रवेश करना भी भारी पड़ रहा है।

सेक्टर 14-15 की विभाजक सड़क से सेक्टर 14 व सेक्टर 15 में प्रवेश करने के लिये कई बार तो आधा घंटा तक भी लग जाता है। इसके चलते स्थानीय पुलिस का काम भी काफ़ी बढ़ चुका है जहां कभी पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं होती थी वहां अब पुलिस, अपने सब काम छोड़ कर यातायात को सुचारु करने में लगी दिखती है।

मुम्बई एक्सप्रेस वे के नाम पर निर्माणाधीन 12 लेन के बाइपास ने तो हालत और भी खराब कर रखी है। इसका दुष्प्रभाव यूं तो सारे यातायात पर पड़ रहा है परन्तु तमाम सेक्टरों की अन्तिम लाइन जो ग्रीन बेल्ट से सटी है, उनकी हालत तो और भी खराब है। पहले तो इनकी आधी ग्रीन बेल्ट ही सड़क में समा गई, उसके बाद सड़क निर्माण के लिये इस्तेमाल हो रही भारी मशीनों ने हालात को और भी बिगाड़ दिया है। जब ये मशीनें चलती हैं तो खिड़कियों के शीशे कम्पन से फड़फ़ड़ाने लगते हैं, मशीनों की आवाज़ से पैदा होने वाली गूंज दिन-रात परेशान करती रहती है।

मोदी-गडकरी का विशेष प्रोजेक्ट होने के चलते यह रात-दिन चलता ही रहता है। तमाम दावों के बावजूद यहां से हर समय धूल के भारी गुबार उठ कर पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करते रहते हैं। प्रदूषण विभाग छोटे-मोटे प्रदूषणकारियों के तो चालान काटता रहता हैं लेकिन सड़कों से उठने वाला गुबार उसे नजर नहीं आता।

निरीक्षण की नौटंकी

दिनांक 6 अप्रैल को एफएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने यहां का दौरा करके शहर की दुर्दशा का अवलोकन किया। शुक्र है कि दो महीने सड़के खुदी रहने के बाद सुधीर जी को फरीदाबाद का ध्यान आया। वास्तव में सुधीर राजपाल फरीदाबाद के अलावा गुड़गांवा महानगर विकास प्राधिकरण के भी सीईओ है। हरियाणा सरकार उन पर इतनी मेहरबान है कि दो-दो शहरों का विकास उनके नाजुक कंधों पर डाल रखा है।

जानकार बताते हैं कि फरीदाबाद सैक्टर-14 में उनका पुश्तैनी घर है और वह यदा-कदा यहां घूमने आते रहते हैं। इसी चक्कर में सड़कों का निरीक्षण भी कर डाला। बताया जाता है कि उन्होंने ठेकेदारों को खूब हड़काया, समय पर काम पूरा करने के लिए उन्हें 'कड़ी चेतावनी' दी, अध बनी सड़कों को भी यातायात के लिए खोलने के लिए कहा। सवाल यह पैदा होता है कि जिस दिन ये ठेके दिये गये उस दिन राजपाल जी क्या कर रहे थे? उन्होंने यह देखने की कोशिश क्यों नहीं की ठेकेदारों की कार्यक्षमता क्या है। जिन ठेकेदारों को कार्यक्षमता से अधिक काम काम दे दिया जाता है तो वह इसी तरह से पूरे शहर को बंधक बनाकर खड़े हो जाते हैं।

भारी भरकम गलती के बाद भी सर्वे कंपनी का तीन करोड़ का बिल किया मंजूर

करनाल। अंबाला में भी इस कंपनी को मिला ठेका। दानवीर कर्ण नगरी में भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार और घोटाले दर घोटाले सामने आ रहे हैं। एक का प्रभाव मिटता नहीं दूसरा सामने आ जाता हैं। करनाल की नगर निगम में पहले दीपक किंगर की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए। इन दिनों नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स आई डी और सर्वे घोटाला प्रकाश में आ रहा हैं। प्रदेश के राजनेताओं की प्रिय कंपनी याशी इन दिनों करनाल के साथ अंबाला में गुल खिला रही हैं। कंपनी की गलतियों का खामियाजा करनाल के एक लाख 29 हजार प्रोपर्टी धारक उठा रहे हैं। लोगों की जूतियां घिस चुकी हैं। लेकिन गलतियों के ठीक होने का नाम नहीं हैं। लोगों का यह भी कहना है कि कंपनी के नुमाइंदे हमारे घर पर मौका देखने आए ही नहीं और घर बैठे बिठाए सर्वे की रिपोर्ट बनाकर भेज दी। नगरनिगम में कोई रास्ता देने को तैयार नहीं हैं। जानकारी के अनुसार करनाल में प्रोपर्टी टैक्स के सर्वे के लिए एक कंपनी याशी को 180 रुपए प्रति घर के हिसाब से एक लाख 69 हजार प्रोपर्टी के सर्वे का ठेका दे दिया। करनाल के कुछ राजनेताओं और अफसरों की चहेती कंपनी याशी ने ड्रोन से सर्वे करवा दिया। कंपनी ने जो सर्वे किया उसके रहते किसी के कमर्शियल को आवासीय, आवासीय को कमर्शियल बना दिया। किसी का प्लाट या मकान किसी के नाम पर। या पता गलत लिखवा दिया।

बताया जाता है कि लगभग एक लाख 29 हजार प्रापर्टी के सर्वे को गलत ठहराया गया हैं। नगर निगम सूत्रों की मानें तो अब तक 69 हजार आपत्तियां मिली हुई है। कई लोगों को पता ही नहीं है। नगरनिगम अफसरों के अनुसार प्रापर्टी में गलती सुधार के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी गलतियों के बाद इस कंपनी के बिल किस तरह से पास हो गए। नगरनिगम अफसरों ने इस कंपनी को ब्लैक लिसटेड क्यों नहीं किया हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री से इस मामले में भाजपा नेता बात करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की नौटंकी जारी, हत्यारा आशीष मिश्रा जेल से बाहर

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

लखीमपुर खीरी में पांच किसानों की योजनाबद्ध हत्या करने वाला मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को लखनऊ हाई कोर्ट ने करीब एक माह पूर्व जमानत पर रिहा कर दिया था। इसके विरुद्ध पीड़ित पक्ष की याचिका को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट नौटंकी करने में जुटी है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत व जस्टिस हिमा कोहली ने सुनवाई के दौरान प्रवचन बघारते हुए कहा कि हाई कोर्ट को मुकदमें के विवरणों में जाने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के लिये कहा कि उसने हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिये जाने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर की? कितनी भोली बनती है सुप्रीम कोर्ट जैसे कि उसे मालूम ही नहीं कि हत्यारे व भाजपा सरकार के बीच क्या रिश्ता है? यहां सुप्रीम कोर्ट पर, 'दूसरों को नसीहत खुद मियां फ़जीहत' वाली कहावत फिट बैठती है।

सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठता है कि जिस दिन हाई कोर्ट ने हत्यारे को जमानत देने का आदेश जारी किया था, उसी दिन उन्होंने हाईकोर्ट से फ़ाइल तलब क्यों नहीं की? उन्हें किसने रोका था? यदि सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उसी दिन फ़ाइल तलब करके हत्यारे की रिहाई रोक सकती थी। इसके अलावा जमानत देने वाले बिके हुए जज पर इस तरह के जमानती केसों की सुनवाई पर रोक लगा सकती थी।

कमाल की बात तो यह है कि पीड़ित पक्ष द्वारा याचिका डालने के तीन सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई का समय निकाला। सुनवाई के बाद आदर्शवादी प्रवचन तो बघार दिये लेकिन जमानत रद्द नहीं की, इसके लिये उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी कि अभी वे और बहुत कुछ सोचेंगे कि जमानत रद्द करनी है या नहीं? इसी को तो कहते है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर इसकी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन-बल्लबगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421